



दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 06 अप्रैल 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 185

महत्वपूर्ण एवं खास

‘परीक्षा पे चर्चा’ पर छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता से बातचीत करेंगे पीएम

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 अप्रैल, 2021 को सायं 7 बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ‘परीक्षा पे चर्चा’ पर दुनियाभर के छात्रों, शिक्षकों एवं माता-पिता से परस्पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, एक नया प्रारूप, विषयों की एक विस्तृत शृंखला पर कई दिलचस्प प्रश्न और हमारे बहादुर Warriors, माता-पिता और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा।

प्रधानमंत्री ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा- स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रबल पैरोकार बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। समाज के शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए उनके प्रभावी प्रयास सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे।

दो मई से पहले चयन समिति की बैठक बुलाए केंद्र : सुको

नई दिल्ली (आरएनएस)। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह जल्द से जल्द सीबीआई निदेशक का चयन करे। इधर केंद्र ने कहा कि निदेशक चुनने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष की चयन समिति दो मई को बैठक करेगी। इस याचिका को कॉमन काउज नाम के एक एनजीओ ने दायर किया था और इसके लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार सीजेआई के रिटायर होने का इंतजार कर रही है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है।

राफेल सौदे की निष्पक्ष जांच हो : सुरजेवाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के मामले में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राफेल विमान सौदे पर सुरजेवाला ने कहा कि 60 हजार करोड़ की सच्चाई सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल विमानों की खरीद में बिचौलियों और कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने यह बात स्वीकार की है कि उसने भारत के साथ राफेल विमान डील में एक बिचौलिया को एक मिलियन यूरो गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग करती है। उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार के पास अब भी वक्त है कि वह इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने इस सौदे पर कहा कि 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फ्रांस, पेरिस के अंदर 60 हजार करोड़



रुपए के 36 राफेल जहाज खरीदने की घोषणा की गई। ना कोडि टेंडर, खरीद प्रक्रिया और ना ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, बस गए और सबसे बड़े रक्षा सौदे की घोषणा कर आए। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, अब स्पष्ट है कि 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में, सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की चमत्कारी गाथा अब देश के सामने है। सुरजेवाला ने मोदी सरकार से पूछे पांच सवाल भी पूछे हैं। 1.1 मिलियन यूरो के जो गिफ्ट दसॉल्ट की ऑडिट रिपोर्ट में मिला। क्या वो राफेल डील के लिए बिचौलियों को कमीशन के तौर पर दिए गए थे? जब दो देशों की सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है, तो कैसे किसी बिचौलिये को इसमें शामिल किया जा सकता है? क्या इस सबके बाद राफेल डील सवालों के घेरे में नहीं आ गया? क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए, जिससे खुलासा हो कि डील के लिए किसको और कितने पैसे दिए गए? क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पर जवाब देंगे?

देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में गड़बड़ी
सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की जांच एजेंसी ने जब कंपनी की जांच की गई तो उसमें कमीशनखोरी के केस सामने आए। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में भारत और फ्रांस की दोनों सरकार की सलिसता बराबर की है।

कंपनी की ऑडिट में हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा
गौरतलब है कि राफेल विमान की खेप भारत में आने शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच फ्रांस की एक वेबसाइट ने राफेल नाम से एक आर्टिकल छपे हैं। इसमें दावा किया गया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहले जानकारी 2016 में फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए

को हुई थी। एएफए ने जांच में पाया कि विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने एक बिचौलियों को 10 लाख यूरो देने पर सहमत जताई है। हालांकि जिस कंपनी को पैसा दिया गया है उसके दलाल एक अन्य हथियार सौदे में गड़बड़ी का आरोपी है।
बिल भारत की कंपनी के नाम पर हुआ तैयार
रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने विमान तैयार करने वाली कंपनी का ऑडिट किया। जिसमें कंपनी के 2017 के खातों की जांच का दौरान क्लाइट को गिफ्ट के नाम पर हुए 1 मिलियन यूरो के खर्च की जानकारी हाथ लगी। इस पर, फ्रांस ने इस खर्च का बिल मांगा तो दसॉल्ट एविएशन ने 30 मार्च 2017 का बिल उपलब्ध कराया। जिसमें भारत की एक कंपनी के नाम पर पैसा मुहैया कराने का उल्लेख है। पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ। हालांकि यह मॉडल बन नहीं पाए। यह बिल राफेल लड़ाकू विमान के 50 मॉडल बनाने के लिए दिए ऑर्डर का आधे काम के लिए था।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हिंसा में शहीद जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि

रायपुर (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर पुलिस लाइन में बीजापुर नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारत सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, केन्द्रीय गृह सचिव ए.के. भल्लू, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डी.एम.अवस्थी, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, डायरेक्टर



आईबी अरविंद कुमार, छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा उपस्थित थे।

दोगुनी गति से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा: शाह

जगदलपुर (आरएनएस)। नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगदलपुर सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक ली, इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। वहीं डीजीपी, आईजी, एस्प्री सहित कई आला अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद अमित शाह ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह सुझाव आया कि किसी भी प्रकार की कमी ना हो, मैं भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि यह लड़ाई रुकेगी नहीं दोगुनी गति से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो विकास कार्य चल रहे हैं, उसमें तेजी लाई जाएगी। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता

उन्मुलन अभियान को आगे ले जाएंगे।
नक्सलियों को भारी क्षति हुई- भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। यह सूचना भी मिल रही है कि नक्सलियों को भारी क्षति हुई है। चार टैक्टर में भर के नक्सली अपने साथियों को ले गए हैं। कुछ दिन में आंकड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कैपों का विस्तार लगातार जारी रहेगा।

पहली बार एक लाख के पार आए कोरोना के नए मामले

» देश में कोरोना संक्रमण का खतरनाक चेहरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में एक दिन में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 1,03,558 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है। वहीं इस दौरान वायरस से 478 मरीजों की मौत हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार के बाद से पिछले साल 17 सितम्बर को एक दिन में सर्वाधिक 97,894 नए मामले सामने आए थे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में वायरस से 478 और



मरीजों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,65,101 हो गई। देश में लगातार 26 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही उपचाराधीन मामलों की संख्या भी बढ़कर 7,41,830 हो गई, जो कुल मामलों का 5.89 प्रतिशत है। देश में 12

फरवरी को सबसे कम 1,35,926 उपचाराधीन मामलों थे, जो उस समय के कुल मामलों का 1.25 प्रतिशत था। आंकड़ों के अनुसार, देश में 1,16,82,136 लोग अभी तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट

आज से रेल पटरियों पर दौड़ने लगी पैसेंजर ट्रेने

नई दिल्ली (आरएनएस)। भले ही देश में कोरोना की नई लहर जोर पकड़ रही है लेकिन रेलवे ने सेवाएं बहाल करने की अपनी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। दरअसल रेलवे ने आज यानी 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेने चलाने का ऐलान किया था। उत्तर रेलवे के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे जोन इन अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलाना शुरू कर दिया है। इससे दिल्ली-एनसीआर के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का समेत कई जगहों की राह आसान करने के लिए उत्तर रेलवे की तरफ से कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। हालांकि कोविड की वजह से ये सभी अनारक्षित ट्रेने स्पेशल ट्रेने के नाम से चलाई जा रही हैं। बोते शनिवार को रेल मंत्रालय ने ऐलान किया था कि रेलवे भारतीय रेल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेने सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। ये ट्रेने यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेंगी। रेलवे के मुताबिक सहारनपुर-दिल्ली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट-लुधियाना, फजिल्का-लुधियाना, बठिंडा-लुधियाना, वाराणसी-प्रतापगढ़, सहारनपुर-नई दिल्ली, जाखल-दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद-पानीपत, शाहजहांपुर-सोतापुर, गाजियाबाद-मुरादाबाद समेत कई शहरों के लिए अनारक्षित ट्रेने चलेगी।

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की योजना सही ढंग से नहीं बनाई गई : राहुल

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की सही तरीके से तैयारी नहीं की गई और इसका क्रियान्वयन भी ‘अयोग्यतापूर्वक’ किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ‘हमारे जवानों को जब चाहे तब शहीद होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।’ गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई



मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए हैं तथा 31 अन्य जवान घायल हुए हैं। राहुल गांधी ने सीआरपीएफ के महानिदेश कुलदीप सिंह के एक बयान से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए कहा, ‘अगर खुफिया नाकामी

नहीं थी तो फिर 1:1 के अनुपात में मौत का मतलब यह है कि इस अभियान की योजना को खराब ढंग से तैयार किया गया तथा अयोग्यतापूर्वक इसका क्रियान्वयन किया गया।’ अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवानों में सीआरपीएफ के आठ जवान शामिल हैं, जिसमें से सात कोबरा कमांडो से जबकि एक जवान बस्तरिया बटालियन से है। शेष डीआरजी और विशेष कार्यबल के जवान हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के एक इंसपेक्टर अब भी लातपात हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने की कृषक उत्पादक संगठनों की योजना की समीक्षा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनने से किसानों की आय बढ़ेगी, इन एफपीओ के बनने से छोटे किसानों को काफी सुविधाएं होगी। देशभर के लगभग 6,600 क्लक हैं और इनमें हरेक में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाएं मिलने के साथ खेती की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ढाई हजार एफपीओ बनाने



का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शन में एफपीओ की इस स्कीम को व्यवस्थित और पारदर्शिता से क्रियान्वित करने एवं सुलभ जानकारी के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात सोमवार को कृषि मंत्रालय में नए एफपीओ की योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कहा। तोमर ने कहा कि एफपीओ के गठन के कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियां एकजुटता व समन्वय के साथ योजना की कल्पना को साकार करें। हमारा उद्देश्य यहीं होना चाहिए कि देशभर के किसानों को इसका पूरा लाभ

मिलें। 10 हजार एफपीओ बनाने पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रूपए खर्च करेगी। उन्होंने एफपीओ की ग्रेंडिंग किए जाने तथा इनमें अधिकाधिक किसानों को जोड़ने की बात कही, ताकि कृषि क्षेत्र को इसका पूरा फायदा मिल सकें। योजना के लिए तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की मदद लेने को भी कहा, जिनका जिलों में काफी नेटवर्क है। बैठक में कृषि राज्य मंत्री परपोतम रूपाला व कैलाश चौधरी ने भी विचार रखें तथा सुझाव दिए। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने योजना की प्रगति से अवगत कराया।

बैठक में बताया गया कि शहद जैसे उत्पाद विशेष के एफपीओ भी बनाए जाएंगे, ऑर्गेनिक उपज के एफपीओ भी बनेंगे। ये एफपीओ बनने से छोटे व सीमांत किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी व उन्हें मार्केटिंग में लाभ मिलेगा। एफपीओ को 18 लाख रूपए की दर से 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी, इकट्टी अनुदान सुविधा भी मिलेगी, जिसमें 15 लाख रू. तक की मैंचिंग इकट्टी ग्रांट होगी। इसी तरह ऋण गारंटी कोष के जरिये प्रति एफपीओ 2 करोड़ रू. तक कोलैटरल फ्री गारंटी सुविधा केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।